दैनिक जागरण

परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है

कश्मीर पर अलग राग

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान किस तरह अलग-थलग पड़ गया है, इसका प्रमाण केवल यही नहीं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि यह भी है कि दक्षिण एशिया का कोई देश उसका साथ देने को तैयार नहीं। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश ने भी जम्मू-कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला करार दिया। इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस ने भी नए सिरे से पाकिस्तान के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि वे कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं समझते। इस सबके बावजूद भारत में कुछ राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस एवं वामपंथी दल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर मीन-मेख निकालने में लगे हुए हैं। क्या इससे अजीब और कुछ हो सकता है कि जब विश्व समुदाय जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है तब कांग्रेस विरोध का राग अलाप रही है और वह भी तब जब उसके एक के बाद एक नेता इस मसले पर पार्टी की राय से असहमति जाहिर कर रहे हैं। यह देखना दयनीय है कि कांग्रेस अभी भी यह मान रही है कि कश्मीर पर मोदी सरकार की कूटनीति विफल है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उसने जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान का सहारा लिया उससे यही स्पष्ट होता है कि वह जम्मू-कश्मीर मामले को समग्रता के साथ देखने के बजाय छिद्रान्वेषण पर जोर दे रही है। शायद यही कारण है कि उसके नेता अनुच्छेद 370 को अस्थाई कहने से बच रहे हैं। कांग्रेसी नेता न केवल इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि यह एक अस्थाई अनुच्छेद था, बल्कि इस बात को भी भूल जा रहे हैं कि खुद नेहरू ने कहा था कि यह संवैधानिक व्यवस्था घिसते-घिसते एक दिन खत्म हो जाएगी।

कांग्रेस को यह स्मरण होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में अनुच्छेद 370 में कई संशोधन किए गए। अगर यह अस्थाई अनुच्छेद इतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी था तो फिर कांग्रेस ने सत्ता में रहते समय उसे स्थाई रूप क्यों नहीं दिया? यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस एक ओर तो कश्मीर को भारत का अटूट अंग बताती है और दूसरी ओर उस अनुच्छेद को हटाए जाने का विरोध भी करती है जो अलगाव और भेदभाव का जरिया बन गया था। बेहतर हो कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि उसे कश्मीर के भारत में एकीकरण को लेकर आपत्ति क्यों है? कायदे से तो यह एकीकरण आजादी के बाद ही होना चाहिए था-ठीक वैसे ही जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों का हुआ था। कांग्रेस सरीखे दल के लिए यह ठीक नहीं कि वह दलगत राजनीतिक हित के आगे देश हित की अनदेखी करे।

हड़ताल से नुकसान

किसी समस्या का समाधान क्या हड़ताल हो सकता है? आज तक क्या हड़ताल या बंद से नुकसान के अलावा किसी का भला हुआ है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर शायद बंगाल में हड़ताल करने वाले कर्मचारियों एवं संगठनों के पास भी नहीं है। यहां बात सेना के लिए हथियार एवं गोला-बारूद बनाने वाली देश की 41 आयुध फैक्ट्रियों के बोर्ड (ओएफबी) के करीब 82 हजार असैन्य कर्मचारियों की एक माह की हड़ताल की हो रही है। देश भर की रक्षा विनिर्माण इकाइयों में मंगलवार से एक महीने की हड़ताल शुरू हो गई है। केंद्र ने हाल ही में इन फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव पास किया है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एक तरफ सेना को मजबूत करने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। यह हड़ताल तीन मजदूर संघों ने की है। वे सरकार की निगमीकरण की योजना तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ कुमार का कहना है कि केंद्र के प्रस्तावित कदम का उद्देश्य फैसले लेने में स्वायत्तता बढ़ानी है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार निगमीकरण या सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के बहाने फैक्ट्रियों का निजीकरण करना चाहती है। यूनियनों की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि निगमीकरण या पीएसयू बनाने से कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि वह आयुध फैक्ट्रियों के निजीकरण नहीं, बल्कि इनको रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम बनाने पर विचार कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'ओएफबी के निजीकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये भ्रामक हैं और इनका मकसद कर्मचारियों को गुमराह करना है।' अगर सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है कि आयुध फैक्ट्रियों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है तो फिर हड़ताल क्यों? क्या सरकार को पता नहीं है कि निजी हाथों में ये फैक्ट्रियों दे दी जाएंगी तो इसका नतीजा घातक भी हो सकता है। क्योंकि आज देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस समय पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि हड़ताली कर्मचारियों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि निजीकरण नहीं हो रहा है और कर्मचारियों को भी बैठकर मसले को सुलझा लेना चाहिए।

हर मोर्चे पर मात खाता पाकिस्तान

विवेक काटजू

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर पर हुई चर्चा का यही निष्कर्ष निकला कि परिषद इस मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है

जम्मू-कश्मीर को लेकर इमरान खान की टिप्पणियों और पाकिस्तान की ओर से उठाए जाने वाले राजनयिक कदमों से लगता है कि पाकिस्तानी नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पाकिस्तान के राजनयिक भी हिंसात्मक रुख अपनाने पर आमादा हैं। जिस दिन से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बदलने की घोषणा हुई उसी दिन से पाकिस्तान एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। इन गलतियों से उसे आज ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत-पाक के बीच यह एक अलिखित परंपरा रही है कि व्यक्तिगत आक्रमण से परहेज किया जाता है। नीतियों और गतिविधियों पर जरूर सख्त रुख अपनाया जाता है, लेकिन कभी भी तीखे निजी हमले नहीं हुए। इमरान खान, उनके साथियों और पाकिस्तानी सेना ने इस उसूल को तिलांजलि दे दी है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की विचारधारा पर जो टिप्पणियां हो रही हैं उन्हें भारत की जनता आसानी से भूल नहीं पाएगी। मोदी भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। भारत की जनता ने उन पर भरोसा किया है। पाक चाहे या न चाहे उसे भाजपा और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ही सामना करना होगा। ऐसे में क्या यह उचित है कि पाकिस्तान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जिससे द्विपक्षीय संबंध कभी सुधर न पाएं? राजनय की हमेशा यह मांग रहती है कि बड़े देशों के नेता नीतियों का खंडन तो करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप का सहारा कभी नहीं लेते। मोदी ने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए इस पूरे घटनाक्रम के बीच न तो इमरान खान पर और न ही पाकिस्तान सरकार के अन्य लोगों पर किसी तरह का निजी हमला किया। इससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए।

पाकिस्तान ने पहले ही भारत के साथ संबंधों को और कमजोर कर दिया है। उसने व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। राजनयिक रिश्तों को कमतर करते हुए भारतीय उच्चायुक्त को स्वदेश लौटने का हुक्म दे दिया और अपने उच्चायुक्त को भारत न भेजने का निर्णय किया। इसके साथ-साथ पाकिस्तान सांस्कृतिक संबंध भी समाप्त करना चाहता है। भारतीय फिल्मों और टीवी प्रोग्राम और यहां तक कि कोई भी विज्ञापन जिसमें कोई भारतीय कलाकार हों, उन्हें दिखाने की पाकिस्तान में अनुमति नहीं रहेगी। ये सब कदम पाकिस्तान की नादानी ही दर्शाते हैं, क्योंकि औपचारिक व्यापार तो खत्म हो सकता है, लेकिन अनौपचारिक व्यापार तो चलता ही रहेगा, भले ही पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। इससे पाकिस्तान की पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था का और बुरा हाल होना तय है। वहीं भारत को इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। जहां तक सांस्कृतिक संबंधों की बात है, पाकिस्तान ने कई बार पहले भी भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वह नाकाम ही रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान भूल जाते हैं कि उनका देश दक्षिण एशिया का भाग है, अरब देशों या ईरान का नहीं। भारत ने दूरंदेशी दिखाते हुए पाक को यह सही सलाह दी कि वह ये सभी नकारात्मक कदम वापस ले, लेकिन शायद दशकों से भरी कटुता पाकिस्तान के नेताओं को तार्किक रूप से सोचने की गुंजाइश नहीं देती।

अवधेश राजपूत

पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की औपचारिक बैठक की मांग की और उसमें बोलने की विशेष अनुमति भी मांगी। उसने यह अनुरोध इसलिए किया, क्योंकि वह परिषद का सदस्य नहीं है। इस पर परिषद के सभापति ने पाक की अपील को ठुकरा दिया। फिर पाक के सदाबहार मित्र चीन ने सभापति से निवेदन किया कि बैठक में अनौपचारिक रूप से चर्चा आयोजित की जाए। यह चर्चा 16 अगस्त को हुई। इस दौरान भारत ने जम्मू-कश्मीर में जो संवैधानिक कदम उठाए उन्हें लेकर चीन को छोड़कर लगभग सभी सदस्यों ने माना कि यह भारत का आंतरिक मामला है। चीन के अलावा करीब सभी देशों में सहमति रही कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भारत-पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाना चाहिए। अमेरिका का यह मत अधिक महत्वपूर्ण था कि इस मामले में सुरक्षा परिषद की कोई भूमिका नहीं। चीन चाहता था कि चर्चा के बाद एक बयान जारी हो, लेकिन फ्रांस और कई अन्य देशों ने यह जारी नहीं होने दिया। चर्चा का यही निष्कर्ष निकला कि आगे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जम्मू-कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है।

यह सच है कि दशकों बाद जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई, लेकिन आज के भारत को ऐसी चर्चा से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे भारत का अंतरराष्ट्रीय रुतबा जाहिर होने के साथ यह भी सिद्ध होता है आज के भारत से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। यह आश्चर्यजनक था कि इस चर्चा में ब्रिटेन की भूमिका नकारात्मक रही। शायद वह अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से पीड़ित है और इसी कारण नए भारत को समझ नहीं पा रहा। ऐसा करके वह अपने हितों की अनदेखी ही कर रहा है। भारत सरकार ब्रिटेन के इस रुख को नजरअंदाज न करे।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने देशवासियों को आगाह किया कि कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन को लेकर वे किसी मुगालते में न रहें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनकी यह आशंका सही साबित हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान इससे सही सबक ले पाएगा? भारत या अंतरराष्ट्रीय समुदाय उससे ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। दरअसल जबसे पाकिस्तान बना तबसे ही भारत के साथ निरंतर शत्रुता उसकी विचारधारा का मुख्य स्तंभ बन गया है। पाकिस्तान के शासकों और प्रमुख रूप से उसकी सेना भारत विरोध की यही घुट्टी पाकिस्तान को पीढ़ी दर पीढ़ी पिलाते आ रही है। भारत के हालिया कदमों से जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के औपचारिक दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह संभव नहीं कि जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी में आने वाले वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन होगा। चूंकि पाकिस्तान कश्मीर पर सार्थक रूप से सोच ही नहीं पाता इसलिए आगे चलकर भी वह नकारात्मक कदम ही उठाएगा। जाहिर है कि भारत को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ अपनी तंजीमों को आतंकवाद की ओर और ज्यादा धकेल सकती हैं। इसके साथ-साथ भारत के विरुद्ध कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने के लिए और भी नई तरकीबें निकाली जा सकती हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को पूर्ण आश्वासन मिले कि उनकी पहचान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। इसके प्रयास किए जाने चाहिए कि वे अपनी पहचान और परंपराओं को पूर्ण रूप से कायम रख सकें।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

दोधारी तलवार पर चलती कांग्रेस

प्रदीप सिंह

यदि चिदंबरम ने कुछ गलत नहीं किया तो किस बात का डर और गलत किया है तो पार्टी क्यों उनका बचाव कर रही है

सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने अपने लेख 'सदाचार का ताबीज' में लिखा है, 'एक राज्य में हल्ला हो गया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने विशेषज्ञों को बुलवाया और जांच करने को कहा। जांच पूरी हुई तो राजा ने कहा दिखाओ भ्रष्टाचार कहां है। विशेषज्ञों ने कहा कि वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर सर्वत्र व्याप्त है। राजा ने कहा कि ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। विशेषज्ञों ने कहा, 'हां महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है।' पिछले चार-पांच दशकों से तो हम लोग भी मानने लगे थे कि भ्रष्टाचार भगवान हो गया है। उसे महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। हम भ्रष्टाचारी की विराटता देखने के इतने आदी हो गए कि हमें वह दिखता ही नहीं था। निराशा ऐसी थी कि भ्रष्टाचार के साथ जीने को नियति मान बैठे। पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री को सीबीआइ की ओर से हिरासत में लिए जाने ने जैसे सपने से जगा दिया। सूक्ष्म भी दिख सकता है यदि देखने और दिखाने वाले में इच्छाशक्ति हो। चिदंबरम पर भ्रष्टाचार का आरोप भगवान तो नहीं बन पाया, पर संस्था जरूर बन गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के मुताबिक चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। जज ने यह बात सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा पेश सुबूतों और दस्तावेजों के आधार पर कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले से पिछले कई दशकों में बनी इस आम धारणा को भी तोड़ा कि देश के कानून की नजर में सब बराबर नहीं हैं। यह भी कि व्यक्ति के रसूख से तय होता है कि कानून के लंबे हाथ की पहुंच उस तक है या नहीं? हाईकोर्ट ने कहा कि सांसद या बड़ा वकील होने से आप कानून से बच नहीं सकते। चिदंबरम और उनकी कांग्रेस पार्टी कई साल से कह रही थी और आज भी कह रही है कि यह सब राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। सो अदालत में भी यही कहा गया, पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहना हास्यास्पद है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर कांग्रेस के वकील नेताओं की फौज सुप्रीम कोर्ट दौड़ी।

चिदंबरम की हालत देखकर महाकवि भूषण की यह कविता याद आती है-तीन बेर खाती थीं, वे तीन बेर खाती हैं। यानी जो दिन में तीन बार खाती थीं अब तीन बेर पर गुजारा कर रही हैं। विडंबना देखिए जिन कांग्रेस नेताओं/वकीलों की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट के ताले आधी रात को खुल जाते थे उनकी पुकार पर शाम साढ़े चार बजे भी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद वह चिदंबरम जो नरेंद्र मोदी सरकार से रोज पूछते थे कि माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कैसे भागा, वही शाम पांच बजे के बाद खुद लापता हो गए। सीबीआइ और ईडी की टीम उनके आवास पर उनका इंतजार करती रही। रात में घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया। सुबह मामला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच के सामने गया तो उन्होंने कह दिया कि मुख्य न्यायाधीश इसे सुनेंगे। इसके बाद भी चिदंबरम कई घंटे लापता रहे।

राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी कांग्रेस पार्टी से शायद कुछ लोगो को उम्मीद रही होगी कि अपनी इस छवि को बदलने के लिए पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं से दूरी बनाकर रखेगी, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं, बल्कि नेहरू-गांधी परिवार की नई नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी चिदंबरम के समर्थन में खुलकर आ गई हैं। इतना ही नहीं, चिदंबरम को पार्टी दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस करने की सुविधा भी दी गई। इसका क्या मतलब समझा जाए कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है या पार्टी और परिवार एक संदेश दे रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे नेता उसकी थाती हैं अथवा यह निकट भविष्य के आसन्न खतरे को देखते हुए अपने लिए समर्थन बनाए रखने की कोशिश है? ध्यान रहे कि नेशनल हेराल्ड मामले में अन्य लोगों के साथ सोनिया और राहुल भी जमानत पर हैं।

चिदंबरम के कानूनी शिकंजे में फंसने से आम लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आएगा। एक धारणा जो मन में घर कर गई थी कि पांच सौ रुपये की रिश्वत लेने वाले सिपाही जैसी छोटी मछलियां तो पकड़ी जाएंगी, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर कभी कोई हाथ नहीं डालेगा। आम आदमी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी हाल में कहा कि राजनीतिक रसूख वालों के खिलाफ सीबीआइ की जांच प्रभावी नहीं होती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ग्रंथि कितने गहरे पैठी हुई है। वैसे बदलाव भारतीय जनतंत्र के उन 'सुल्तानों' की सोच में भी आएगा जो मानकर चलते थे कि उनके ऊपर हाथ डालने की किसी में हिम्मत नहीं है। उन्हें यकीन था कि सत्ता में कोई हो, सिस्टम उनका दास है। उनका यह यकीन मुगालता साबित हो रहा है। चिदंबरम और कांग्रेस नेताओं की बदहवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अच्छी है। कानून का डर होना ही चाहिए। केवल आम आदमी को ही कानून से क्यों डरना चाहिए। रसूख वालों का यह डर अच्छा है। इससे गरीब आदमी को सुकून मिलेगा कि कानून की नजर में सचमुच सब बराबर हैं।

कांग्रेस ने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं, पर संगठन मजबूत स्थिति में हो तो गलती का नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम का बचाव करने का फैसला करने से पहले पार्टी कार्यसमिति की बैठक नहीं हुई। मां सोनिया और बेटे राहुल की बैठक में तय हुआ कि चिदंबरम का बचाव करना है और पूरी पार्टी बचाव में कूद पड़ी। ऐसा लगा जैसे चिदंबरम भ्रष्टाचार के आरोपी न होकर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही हों। सवाल है कि पार्टी के युवा नेता जिनका अभी लंबा राजनीतिक जीवन है, वे भ्रष्टाचार के इस दाग को क्यों ढोएंगे? जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे पर पार्टी के अंदर से निकली बगावत की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि पार्टी ने एक और आत्मघाती फैसला ले लिया। इस फैसले से कांग्रेस आम लोगों को बता रही है कि सत्ता में रहते हुए उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसकी वास्तविकता को नजरअंदाज कर, वह बचाव करेगी। यदि चिदंबरम ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर कैसा और गलत किया है तो बचाव क्यों? कहते हैं इस जीवन का किया-अनकिया सब यहीं रहता है। कांग्रेस और चिदंबरम दोनों, जीवन की इस सच्चाई से भाग रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कबीर दास बहुत पहले लिख गए हैं-'करम गति टारै नाहीं टरी..।'

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेम

मनुष्य ऐसी किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम कर सकता है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करता हो। ऐसा प्रेम एक-दूसरे के लिए सिर्फ चाह या दिखावा मात्र नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली भाव-संबंध है। प्रेम में मनुष्य के भीतर एक अहसास उत्पन्न होता है और इसी अहसास के अनुरूप वह व्यवहार भी करता है। कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़कर कोई विद्वान नहीं होता, लेकिन जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले, वह महापंडित हो जाता है। यह संसार मिथ्या है और यहां दुखों का अंबार लगा है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य को अपने जीवन के प्रति विशेष लगाव है। इसका कारण यही है कि संसार में अवश्य ऐसा कुछ आकर्षण है कि लोग दुखों को सहने को भी तैयार रहते हैं। संसार का यह आकर्षण प्रेम ही है और प्रेम के अभाव में मनुष्य के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मनुष्य के जीवन में आनंद का आधार प्रेम ही है। प्रत्येक धर्म-संस्कृति में प्रेम के गुण को सर्वोच्च माना गया है। प्रेम, ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ गुण है और इसी गुण के कारण हम उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं।

भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हजारों दीयों को एक ही दीये से, बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है, उसी तरह खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। वह कहते हैं कि आंख के बदले आंख की मंशा पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। घृणा, घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है, यही शाश्वत नियम है। असल में जब हम स्वयं से प्रेम करने का संकल्प लेते हैं, तभी हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। ऐसा तब तक संभव नहीं, जब तक मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त न कर ले। जब मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित और दूसरों को क्षमा प्रदान करता है, तभी वह ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। क्षमा ही हमारे प्रेम की क्रिया है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए करनी होती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब वास्तव में हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते हैं।

आचार्य अनिल वत्स

धर्म का सही मतलब

डॉ. रतन कुमार घोषाल

भारत में धर्म का अर्थ वह नहीं है जो विपक्षी दल लगा रहे हैं। इसका सीधा आशय राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना से है

भारत विश्व के समस्त देशों में एक अनोखा गणतंत्र है। यहां भौगोलिक, भाषागत विविधत होने के बावजूद इसकी जनतांत्रिक बुनियादी संरचना किसी चट्टान के समान मजबूत है। यह मजबूती इसे राष्ट्रवाद की भावना से मिली है जो इसके कण-कण में समाहित है। यह भी सत्य है कि अनेक उन्नत देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय अभी काफी कम है। मानव विकास सूचक में भी भारत का स्थान काफी नीचे है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी संरचना भी उन्नत नहीं है। गरीबी भी भयावह है। इसके बावजूद यहां केंद्रीय और राज्यों के स्तर पर चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होते रहे हैं। दुख की बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र में समय के साथ कई बुराइयां प्रवेश कर गई हैं। अधिकांश राजनीतिक दल इन्हें दूर करने के बजाय इनको ही सत्ता प्राप्ति का जरिया बना लिए हैं। इधर भाजपा जब से केंद्र में सत्ता में आई है तब से विपक्षी दल उस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। बंगाल में इन दिनों यह कुछ ज्यादा देखने-सुनने को मिल रहा है। विपक्ष के इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या विरोधी दल के नेता भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का असली अर्थ समझते हैं? या फिर वे पूजा-पाठ की पद्धति को ही असली धर्म मान बैठे हैं?

गीता में कहा गया है कि मनुष्य की प्रकृति और उसके संभावित कर्म का सटीक संपादन ही धर्म है। बंकिमचंद्र के शब्दों में कहें तो मानव प्रवृत्ति का साधन ही धर्म है। उन्होंने देश प्रेम को ही धर्म माना और इसे राष्ट्रीयता के आंदोलन से जोड़ा। उनका 'वंदेमातरम्' मंत्र भारतवासियों में 'ब्रह्मत्व' का विकास करने में सक्षम हुआ था। वास्तव में हिंदुत्व और धर्म किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होता है। सनातन हिंदू धर्म के मूल में स्नेह और प्यार हैं। अर्थात स्वयं को सर्वभूत देखना और सर्वत्र समान देखना यही धर्म है। भारत में कई तरह की विविधताएं हैं। यहां विभिन्न भाषाएं, विभिन्न विचार, विभिन्न पहनावा आदि हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इसे सांप्रदायिक विभाजन नहीं माना जाना चाहिए। संप्रदाय का मतलब यदि दल अथवा समूह होता है तो समस्त राजनीतिक दल ही सांप्रदायिक हैं, क्योंकि सभी एक-दूसरे के विरुद्ध बोल और कार्य कर रहे हैं। श्रमिक संप्रदाय और मालिक संप्रदाय के बीच विरोध उत्पन्न करना भी तो सांप्रदायिकता है।

वास्तव में भारत धर्म आधारित देश है। इसलिए तो ऋषि अरविंद ने कहा था कि धर्म के लिए, धर्म द्वारा ही भारत का आस्तित्व है। और यहां धर्म का मतलब उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना माना है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में धर्म का व्यापक अर्थ वह नहीं है जो विपक्षी दल लगा रहे हैं। इसका सीधा आशय राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना से है। भाजपा इसी विचारधारा को मानती है। बंगाल के लोग इससे प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ रहे हैं। गत चुनावों में इसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी इसका प्रमाण है। बंगाल के दूसरे दलों को भी इससे सीखना चाहिए और बेवजह धर्म के नाम पर इसे बदनाम नहीं करना चाहिए।

(लेखक कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

मेलबाक्स

स्याह तथ्यों वाला लेख

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का आलेख 'स्याह नतीजों वाला फैसला' पढ़ा। वह लिखते हैं कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच राजनीतिक दीवार को गिराकर कश्मीर को सीधे नई दिल्ली से संचालित किया जाना उचित नहीं है। मेरा उनसे सवाल है कि क्यों कांग्रेस सरकारों में जम्मू-कश्मीर को जनवरी 1990 से अक्टूबर 1996 तक, यानी पौने सात साल तक राष्ट्रपति शासन में रखकर दिल्ली से सीधे संचालित किया गया था? यह संविधान के अनुच्छेद 356 में दो-दो बार संशोधित करके किया गया था। इसी तरह पंजाब को 1987 से 1992 के बीच पांच वर्ष राष्ट्रपति शासन के तहत रखा गया था। वह आगे लिखते हैं कि जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 1951 में संविधान सभा का गठन किया गया और उसके द्वारा बनाया गया सूबे का संविधान 26 नवंबर, 1957 को लागू हुआ। पहली बात तो यह है कि लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1957 थी। और वहां की संविधान सभा के गठन के बारे में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उसका 75 सदस्यीय सदन एक ही पार्टी यानी नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं से भरा पड़ा था, अन्य किसी दल को या तो चुनाव में खड़े ही नहीं होने दिया गया या जीतने नहीं दिया गया। इसके लिए सरकारी मशीनरी का सीमा से परे जाकर दुरुपयोग किया गया। हिंदू-बौद्धों के हितों का ध्यान रखने वाला वहां कोई नहीं था। जम्मू तथा लद्दाख के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया कि कश्मीर घाटी ही सर्वोच्च बना दी गई। दोनों की आबादी मिलाकर घाटी से अधिक थी, किंतु घाटी को विधानसभा में 47 सीटें और जम्मू-लद्दाख को 41 स्थान दिए गए। लोकसभा में भी घाटी के लिए तीन और जम्मू-लद्दाख के लिए भी तीन स्थान रखे गए। जम्मू-कश्मीर संविधान इसीलिए एक क्रूर प्रहसन है। लगता है कि लेखक को उस विलय पत्र के विषय में भी पूरा ज्ञान नहीं है, जिस पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। यह अन्य 554 विलयपत्रों के ही बिल्कुल समान था, जिनके द्वारा शेष रियासतों ने भारत में अधिमिलन किया। इस विलयपत्र के प्रावधानों से परे जाते हुए केवल कश्मीर के संबंध में 370 की व्यवस्था करते समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन गोपालस्वामी आयंगार ने सदन को आश्वस्त किया था कि 370 एक अस्थायी व्यवस्था है जो जल्दी समाप्त हो जाएगी। आखिर वह अस्थायी व्यवस्था कब तक चलती?

अजय मित्तल, मेरठ

जनसंख्या नियंत्रण

20 अगस्त के अंक में हृदय नारायण दीक्षित का लेख, राष्ट्रीय समृद्धि से जुड़ा है जनसंख्या नियंत्रण, पढ़ा। लेखक की चिंता वाजिब है। आज जनसंख्या के कारण बड़ी-बड़ी सड़कें, अस्पताल, स्कूल व शिक्षण संस्थान सब छोटे पड़ रहे हैं। एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी के पास ना घर है, ना पीने का पानी और ना टॉयलेट। अतः अब जनसंख्या नियंत्रण निहायत जरूरी हो गया है।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम

दिल्ली में बाढ़ और कारण

इस समय दिल्ली में बिना बारिश के बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। 23 हजार से ज्यादा लोग यमुना के आसपास से हटाए गए हैं। इससे पहले दिल्ली में 1978 में भयानक बाढ़ आई थी। दिल्ली में बाढ़ के कारण प्राकृतिक कम और मानवीय ज्यादा हैं। दिल्ली के यमुना नदी के आसपास अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं। यमुना नदी के पास भूमि माफिया ने जमीन काट कर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे यमुना के किनारे सिकुड़ गए हैं। सरकार ने 1000 करोड़ से ज्यादा रुपये यमुना की सफाई पर खर्च कर दिए हैं, लेकिन यमुना आज भी नाले जैसी ही प्रतीत होती है। अगर सरकार जल प्रबंधन को सही ढंग से लागू करे तो यमुना के आसपास बेहतरीन नाले नहर बनाकर पानी को बाढ़ के समय उसमें डाला जा सकता है जिससे दिल्ली में बाढ़ का संकट भी खत्म हो जाएगा और पानी की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

पाक का कश्मीर राग

जब से भारत एवं पाकिस्तान पृथक स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं, तब से पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है। अब भारत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाक अधिकृत कश्मीर पर दावा पेश करना चाहिए। यह भारत का अभिन्न अंग है। इसे लेकर भारत को आवाज उठाने की जरूरत है। यह व्यावहारिक एवं नैतिक कदम होगा।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।